सं.ग्रो.वि./एफ.डी./22-85/29668.—चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राये है कि मैं. एवन सर्विसेज (प्रोएण्ड एजन्सीज) प्रा. लि. पाली रोड़, बल्लबगढ़ के श्रमिक श्री बुद्धि राम तथा प्रबन्धकों के मध्य इसमें इसके बाद लिखित मामले में कोई ग्रौद्योगिक विवा द है,

ग्रौर चुंकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं।

इस लिए, ग्रव, ग्रौद्योगिक विवाद ग्रिधिनियम, 1947 की धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (ग) द्वारा प्रदान की गई शिक्तयों का प्रयोग करते हुए, हिरयाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी ग्रिधिसूचना सं. 5415—3—श्रम 68/15254, दिनांक 20 जून, 1968 के साथ पढ़ते हुए ग्रिधिसूचना सं. 11495—जी—श्रम 57/11245 दिनांक 7 फ़रवरी, 1958 द्वारा उक्त ग्रिधिसूचना की धारा 7 के ग्रिधीन गठित श्रम न्यायालय फ़रीदाबाद को विवादग्रस्त या उससे सुसंगत या उससे सम्बन्धित नीचे लिखा मामला न्यायिनिर्णयत के लिये निर्दिष्ट करते हैं जो कि उक्त प्रवन्धकों तथा श्रमिक के बीच या तो विवादग्रस्त मामला है या विवाद से सुसंगत ग्रथवा संबंधि मामला है :—

क्या श्री बुद्धि राम की सेवाओं का समापन न्यायोचित तथा ठीक है, यदि नहीं तो वह किस राहत का हकदार है ?

सं ग्रो.वि./एफ.डी./141-85/29682- चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राये है कि मै एस० जे० विटिंग एण्ड फिनिशिंग मिल प्रा०लि०, 13/7, मथुरा रोड, फरीदाबाद केश्रमिक श्री धर्मवीर सिंह तथा उसके प्रबन्धकों के मध्य इसमें इसके बाद लिखित मामले में कोई ग्रीदयोगिक विश्वाद है।

ग्रीर चंकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं;

इसलिये, ग्रब ग्रौद्योगिक विवाद श्रिवित्यम, 1947 की घारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (ग) द्वारा प्रदान की गई शिक्तयों का प्रयोग करते हुये हिरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी ग्रिविस्चना सं. 5415-3-श्रम-68/15254, दिनांक 20 ज्न, 1968 के साथ पढ़ते हुए श्रिविस्चना सं. 11495-जी-श्रम/57/11245, दिनांक 7 फरवरी, 1958 दारा उनैत ग्रिविस्चना की घारा 7 के ग्रधीन गठित श्रम न्यायालय फरीदाजाद को विवादग्रस्त या उससे सुमंगत या उससे सम्बन्धित नीचे लिखा मामला न्यायनिर्णय के लिए निर्दिष्ट करते हैं जो कि उन्त प्रबन्धकों तथा श्रमिक के बीच या तो विवादग्रस्त मामला है या विवाद से सुसंगत ग्रथवा सम्बन्धित मामला है:

च्या श्री धर्मवीर सिंह की सेवाग्रों का समापन न्यायोचित तकाठीक है? यदि नहीं तो वह किस राहत का हकदार है?

सं स्रो.वि./एफ.डी./७2-85/29689.—चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राये है कि मै.गुडईयर लि० बल्लबगढ़, के श्रमिक श्री बाबू राम श्री तथा उसके प्रबन्धकों के मध्य इसमें इसके बाद लिखित मामले में को ग्रीद्योगिक विवाद है,

ग्रौर चूंकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं ;

इसलिए, ग्रब, ग्रौद्योगिक विवाद ग्रिधिनियम, 1947 की धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (ग) द्वारा प्रदान की गई शिक्तयों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी ग्रिधिसूचना सं. 5415-3-श्रम-68/15254, दिनांक 20 जून, 1968 के साथ पढ़ते हुए ग्रिधिसूचना सं. 11495-जी-श्रम/57/11245, दिनांक 7 फ़रवरी, 1958 द्वारा उक्त ग्रिधिसूचन की धारा 7 के ग्रिधीन गठित श्रम न्यायालय फ़रीदाबाद को विवादग्रस्त था उससे सुसंगत या उससे संबंधित नीचे लिखा मामला न्यायिन्ण्य के लिए निदिष्ट करते हैं जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिक के बीच या तो विवादग्रस्त मामला है या विवाद से सुसंगत ग्रथया संबंधित मामल है:—

क्या श्री बाबू राम की सेवाग्रों का समापन न्यायोचित दूथा ठीक है ? यदि नहीं तो वह किस राहत का हकदार है ?

संस्रो वि./एफ.डी./48-85/29703--चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि मैं. 1. परिवहन स्रायुक्त हरियाणा (2) महा प्रबन्धक हरियाणा राज्य परिवहन फरीदाबाद, के श्रमिक श्री रूप चंद परिवालक नं 288/103 तथा उसके प्रबन्धकों के बीच इसमें इसक बाद लिखित मामले में कोई स्रौद्योगिक विवाद है;

ग्रीर चूंकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं;

इसलिए, श्रव, श्रौद्योगिक विवाद श्रिधिनियम, 1947 की धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (ग) द्वारा प्रदान की गई शिक्तयों का प्रयोग करते हुये, हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी श्रिधिसूचना सं. 5415-3-श्रम-68/15254, दिनांक 20 जून, 1968 के साथ पढ़ते हुए श्रिधिसूचना सं. 11495-जी-श्रम/57/11245, दिनांक 7 फरवरी, 1958 द्वारा उक्त श्रिष्ठिसूचना की धारा 7 के श्रधीन गठित श्रम न्यायालय, फरीदाबाद को विवादग्रस्त या उससे सुसंगत या उससे संबंधित नीचे लिखा मामला न्यायिनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करते हैं जो कि प्रबन्धकों तथा श्रमिक के बीच या तो विवादग्रस्त मामला है या विवाद से सुसंगत श्रथवा संबंधित मामला है :—

क्या श्री रूप चंद की सेवाग्रों का समापन न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं तो वह किस राहत का हकदार है ?